

फा.सं. 48013/1/2012-मा. (समन्वय), खंड- III (ई-3595)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग

पहली मंजिल, 36, जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक 18 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मत्स्यपालन विभाग के संबंध में मंत्रियों/विभागों द्वारा जून, 2022 में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख गतिविधियों के मासिक सारांश का परिचालन

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 अगस्त, 2019 के कैबिनेट सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/1/2018-कैब को संदर्भित करने और आपकी जानकारी के लिए जून, 2022 के लिए मत्स्यपालन विभाग का मासिक सारांश परिचालित करने के निदेश हुआ है जिसमें कृत मुख्य गतिविधियां, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की प्रगति उल्लिखित है ।

संलग्नक : यथोपरि

(डॉ. एंसी मैथ्यू एनपी)

सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि

- 1) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली-110001 (ध्यानाकर्षण: श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक)
- 2) प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव
- 3) राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- 4) उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
- 5) प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- 6) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव,
- 7) सलाहकार, कृषि कार्यक्षेत्र, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- 1) माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के निजी सचिव
- 2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के माननीय राज्यमंत्री के निजी सचिव
- 3) सचिव, मत्स्यपालन विभाग के प्रधान निजी सचिव
- 4) अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
- 5) मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिवों, के प्रधान निजी सचिव
- 6) तकनीकी निदेशक, एनआईसी डीओएफ को विभाग की वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेज अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग में जून, 2022 माह के

दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां

1. माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (एफएएचडी) ने 7 जून, 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया ।
2. 21 जून, 2022 को केदारनाथ, उत्तराखंड में इस विभाग द्वारा 8 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया गया। डॉ संजीव कुमार बाल्यान, माननीय राज्यमंत्री, एफएएचडी इस अवसर के मुख्य अतिथि थे और कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। भारत की आजादी के 75 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में दैनिक जीवन में योग के महत्व पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इस विभाग के सभी संबद्ध कार्यालयों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।
3. 14 जून, 2022 को माननीय राज्य मंत्री (एफएएचडी और आई एंड बी) ने, काकीनाडा जिले, आंध्र प्रदेश में विभिन्न मात्स्यिकी परियोजनाओं का निरीक्षण किया और हितधारकों के साथ बातचीत की । उन्होंने लाभार्थी बातचीत कार्यक्रम के दौरान उद्यमिता मॉडल और पोम्पानो फिश कल्चर पर ब्रोशर भी जारी किया ।
4. 15 जून, 2022 को विभाग ने संसद भवन एनेक्सी में "बाल श्रम की राष्ट्रीय नीति का अवलोकन-एक समीक्षा" पर चर्चा करने के लिए श्रम, कपड़ा और कौशल पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया और समिति द्वारा दिए गए सुझावों को आगे की कार्रवाई के लिए नोट किया ।
5. "मात्स्यिकी और जलीय कृषि में नई तकनीक को अपनाना" विषय पर एफएएचडी मंत्रालय की सलाहकार समिति की अंतर-सत्र बैठक 30 जून, 2022 को संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली

में आयोजित की गई थी। विभाग नें मात्स्यिकी और जलीय कृषि में नई प्रौद्योगिकी के बारे में समिति को जानकारी दी और समिति के सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया।

6. 12 जून 2022 से 17 जून 2022 तक जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में विभाग ने प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भाग लिया और विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर मतभेदों को कम करने और सर्वसम्मति लाने की दिशा में सक्रीय रूप से काम किया, जिससे 17 जून, 2022 को मत्स्य सब्सिडी पर ऐतिहासिक समझौते को अपनाया गया। वार्ता के दौरान, भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल वाटर्स और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र दोनों) और आरएफएमओ (क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन) समझौते के अंतर्गत आने वाले अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रहे पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों को सब्सिडी देने के अपने अधिकार का सफलतापूर्वक बचाव और संरक्षण किया। समझौते में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं अवैध, सूचित न किया गया और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी को खत्म करना और ओवरफिशड स्टॉक में मछली पकड़ने वालों के लिए सब्सिडी को प्रतिबंधित करना और आरएफएमओ क्षेत्रों के बाहर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर सब्सिडी को समाप्त करना है। यह उम्मीद की जाती है कि इन उपायों से बड़े पैमाने पर अंधाधुंध औद्योगिक मछली पकड़ने पर अंकुश लगेगा और मछली के स्टॉक को पुनर्जीवित होने में मदद मिलेगी, इस प्रकार छोटे पैमाने पर तटीय मत्स्यन को मदद मिलेगी।

7. विभाग ने आईसीएआर- नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सज (एनबीएफजीआर) के सहयोग से 'नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज (एनएसपीएडी)' के कार्यक्रम को मजबूत और विस्तारित करने के लिए कदम उठाए और 3 वर्ष की अवधि के लिए पीएमएमएसवाई के तहत राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से एनएसपीएडी चरण-II के कार्यान्वयन के लिए एनबीजीएफआर को 33.77 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की।

इसके परिणामस्वरूप रोग निगरानी प्रणाली में सुधार और त्वरित उपचारात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से जलीय कृषि के लिए रोग जोखिम को कम करने की उम्मीद है।

8. जलीय कृषि प्राधिकरण (सीएए) ने जून, 2022 के महीने में पंजीकरण के लिए 578 आवेदनों और जलीय कृषि फार्मों के नवीनीकरण के लिए 53 आवेदनों और एक्वा इनपुट निर्माताओं और वितरकों की 31 कंपनियों के 113 आवेदनों को जून 2022 के दौरान एंटीबायोटिक मुक्त पदार्थों के अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मंजूरी दी । इसके अलावा जून, 2022 के दौरान एंटीबायोटिक मुक्त पदार्थों के अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, सीएए ने फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए 299 आवेदनों, झींगा हैचरी के पंजीकरण और पंजीकरण नवीनीकरण के लिए 7 आवेदन और एक्वा इनपुट निर्माताओं और वितरकों की 9 कंपनियों से 30 आवेदनों को भी संसाधित किया।
9. एनएफडीबी ने जून, 2022 के महीने में 17723 व्यक्तियों को कवर करते हुए विभिन्न मीडिया के माध्यम से 54 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया। राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (निफफेट) ने महीने के दौरान 173 प्रशिक्षु दिनों में शामिल उन्नीस (19) समुद्री मछुआरे महिलाओं / पुरुषों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
10. केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) ने अपने नियमित पाठ्यक्रम चलाने के अलावा 139 समुद्री मछुआरों के लिए दो (2) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थागत प्रशिक्षुओं और पोस्ट संस्थागत प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो खोजपूर्ण मात्स्यिकी प्रशिक्षण पोत रवाना हुए ।
11. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्टल इंजिनियरिंग फॉर फिशरी ने महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के जीवन और भारखोल और रत्नागिरी जिले के हरनाई और सखारी नाटे में चार (4) मछली पकड़ने के बंदरगाहों के निर्माण के लिए डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की ।

12. संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) ने 27 जून, 2022 से 1 जुलाई, 2022 तक लिस्बन, पुर्तगाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में डॉ. जितेंद्र सिंह माननीय राज्य मंत्री और एमओईएस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भाग लिया और "मात्स्यिकी को स्थायी बनाना और छोटे पैमाने/पारम्परिक मछुआरों को समुद्री संसाधनों और बाजारों तक पहुंच प्रदान करना" विषय पर भाषण दिया।
13. मत्स्यपालन विभाग ने जून 2022 के दौरान गुजरात में विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ़) पेनियस मोनोडोन श्रिम्प (टाइगर श्रिम्प) के लिए निजी क्षेत्र में नई ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन (बीएमसी) सुविधा के संचालन को मंजूरी दी। इससे झींगा जलीय कृषि के विविधीकरण में काफी मदद मिलेगी और टाइगर झींगा कृषि और निर्यात के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, विभाग ने आंध्र प्रदेश में एसपीएफ़ लिटोपेनियस वन्नामेई झींगा के प्रसार के लिए निजी क्षेत्र में एक और बीएमसी की स्थापना को भी मंजूरी दी।
14. तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार ने इस विभाग की सलाह के आधार पर जलीय कृषि में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स के गठन को अधिसूचित किया।
15. 17 जून 2022 को एनएफडीबी, सीए और एमपीईडीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सह विचार मंथन बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ भारत से मात्स्यिकी निर्यात बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर किया गया था।
16. मत्स्यपालन विभाग ने यूएस-एनओए (नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए तीन साल की अवधि के लिए पीएमएमएसवाई के तहत "भारत में समुद्री स्तनपायी स्टॉक आकलन" / "मरीन मैमल स्टॉक अससेसमेंट इन इंडिया" के लिए भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, एमपीईडीए और आईसीएआर सीआईएफटी को 7.10

करोड़ की एक सहयोगी परियोजना को मंजूरी दी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका में प्रकृतिकृत पकड़ी गई समुद्री मछलियों के निर्यात पर कोई गैर-टैरिफ बाधा नहीं डालता है।

17. मत्स्यपालन विभाग ने हितधारकों के साथ नियमित बातचीत की एक प्रणाली शुरू की है। 23/06/2022 को, मछुआरों और जलीय कृषि किसान संघों के साथ बीज और चारा उत्पादकों, निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, घरेलू व्यापारियों और ऑनलाइन विपणक के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई; राज्य सहकारी संघों और फिशिंग गियर निर्माताओं के साथ आगे की बैठकें क्रमशः 24/06/2022 और 28/06/2022 को आयोजित की गईं।
18. विभाग ने 26/06/2022 को आईसीएआर मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों, राज्य मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें मात्स्यिकी से संबंधित प्रौद्योगिकियों के संचालन पर चर्चा की गई जो उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं, और अगले 2 वर्षों के लिए अनुसंधान के लिए क्षेत्रों को तैयार कर उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं ।
19. जन शिकायत: जून, 2022 तक मत्स्यपालन विभाग के सीपीजीआरएमएस पोर्टल में शिकायत निपटान 94% था ।